ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : मध्य प्रदेश में 1991-92 में 5500 गांवों और 1992-93 में 7912 गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने की संभावना है।

Rural based Industrial Units

3287. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government are contemplating to build up Rural based Industrial Units with a view to encourage agriculturists family;

(b) whether the above said rural based industrial units would be on the model of Japanese where the entire family is engaged; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Government of India have been following the policy to promote rural and cottage industrial units with a view to stepping up non farm employment opportunities in rural areas.

(b) No.

(c) Question does not arise.

Construction of Houses for rural poor and middle class people

3288. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the plan of Government to accelerate the construction of houses in the country specially for poor and middle class people in the rural areas; and

(b) by when Government plan to provide roof over the head of every citizen of the country, indicating the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Housing is the subject in the State Sector and States/UTs are implementing their own housing programmes. At the national level, there are two housing schemes in operation in the rural areas viz., the scheme of allotment of housesite-cum-construction assistance and Indira Awas Yojana (IAY).

Under the scheme of housesite allotment-cum-construction assistance housesites are allotted to rural landless workers and construction assistance is provided for construction of houses on such allotted house sites. Under Indira Awas Yojana houses are provided free of cost to the target group consisting of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and freed bonded labourers below the poverty line in rural areas.

Besides Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) provides housing loans for persons belonging to Economically Weaker Sections (EWS) and Low Income Group (LIG) in rural areas.

(b) Keeping in view the high magnitude of housing shortage, which has been projected to be 30.30 million dwelling units, comprising of 10 million dwelling units in urban areas and 20.30 million dwelling units in the rural areas as on 1-3-1990, it is not possible to fix a date by which all the people in the country could be provided houses.

Roads in Villages

3289. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government share fifty per cent of the total cost which is incurred by a State in connecting the roads of villages in the State;

(b) if so, how much amount has been given to Madhya Pradesh during the last three years on this account and how many village roads have been connected with each other during the said period;

(c) whether Madhya Pradesh has asked for more funds in this connection; and

(d) what action Government has taken on that demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) No, Sir. The construction of roads including rural roads is a State subject under Minimum Needs Programme (MNP) and funds for the same are being provided in the State Plan/Budget.

(b) to (d) Does not arise.

डकैती उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन सड़कों का निर्माण

@3290. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश के डाकू ग्रस्त जिलों में डकैती उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन प्रथम चरण के अंतर्गत 14 सड़कों के निर्माण और द्वितीय चरण के अंतर्गत 61 सड़कों के निर्माण हेतु क्रमशः वर्ष 1984 तथा 1985 में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त सभी सड़कों के निर्माण के लिये धन को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी सड़कों के निर्माण के लिये कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच० पटेल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना रिपोर्ट में विशेष समस्या वाले क्षेत्रों (जिन्हें पहले दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता था) में सड़कों के निर्माण की योजना के अंतर्गत पहले चरण में 14 सड़कों और दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण हेतु अनुमान शामिल किए गए थे। इसमें से, दूसरे चरण की एक सड़क सहित 14 सड़कों को 1985–86 और 1986–87 में अनुमोदित किया गया है। सभी निर्माण कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश सरकार से 10 अन्य सड़कों के निर्माण का भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पहले से स्वीकृत निर्माण-कार्यों की असन्तोषजनक प्रगति और राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण न मिलने के कारण 10 सड़कों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका था।

इन सड़कों के लिये प्रशासनिक अनुमोदन स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति, निधियों की उपलब्धता और राज्य सरकार से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश के विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव

@@3291. **श्री अजीत जोगी :**
श्री बेकल "उत्साही :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से राज्य की जनजातीय पट्टी में स्थित विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये तकनीकी तथा वित्तीय मंजूरी देने के लिये वर्ष 1983 में 119 करोड़ रुपये के प्राक्कलन प्राप्त हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने इन प्राक्कलनों को मंजूरी दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो वांछित स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) सड़कों के निर्माण हेतु 119.22 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक मास्टर प्लान मध्य प्रदेश सरकार से 1983 में प्राप्त हुई थी। उस समय राज्य सरकार से इस

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2599, 16 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित।

@@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2579, 16 दिसम्बर, 1991 से स्थानान्तरित।